THE CURRENTS

UPSC करेंट अफेयर्स · हिन्दी संस्करण · HINDI EDITION

2026-03-12

इस अंक में

#01 सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया में अंतर स्पष्ट किया

#02 गेनबिटकॉइन घोटाला मामले में सीबीआई ने डार्विन लैब्स के सह-संस्थापक आयुष वर्ष्णेय को गिरफ्तार किया

#03 कैबिनेट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता और कंपनी अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दी

#04 एसआरएमआईएसटी ने नौसेना अकादमी के साथ तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

#05 आरबीआई ने ₹50,000 करोड़ की जी-सेक्स खरीद की

#06 किसान निधि की अगली किश्त 13 मार्च को किसानों के खाते में आएगी

#07 भारतीय घरों में इंडक्शन स्टोव की धीमी गति

#08 इरान ने क्षेत्र में अमेरिकी-इज़राइली आर्थिक, बैंकिंग हितों पर निशाना साधने की घोषणा की

#09 जॉन डीरे ने 130 एचपी ट्रैक्टर ₹65 लाख में लॉन्च किया

#10 मुख्यमंत्री कोच्चि में ₹3,509 करोड़ के मैरीन ईको सिटी परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे

राजनीति एवं शासन

#01

सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया में अंतर स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया के बीच के अंतर को स्पष्ट किया, जिसमें उन्होंने एक्टिव यूथेनेशिया को एक नई, बाहरी एजेंसी के नुकसान के माध्यम से मृत्यु का कारण बताया। इसके विपरीत, उन्होंने पैसिव यूथेनेशिया को मृत्यु को होने देने के रूप में समझाया। यह अंतर यूथेनेशिया की जटिलताओं को समझने में महत्वपूर्ण है। जज की यह स्पष्टीकरण मरने के अधिकार और चिकित्सा नैतिकता पर चल रही बहस के बीच आया है। सुप्रीम कोर्ट यूथेनेशिया के मुद्दे और इसके व्यक्तिगत अधिकारों और चिकित्सा नैतिकता पर प्रभाव की जांच कर रहा है।

पृष्ठभूमि

> *भारत में यूथेनेशिया की अवधारणा पर कई वर्षों से चर्चा हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी। फैसले ने कertain शर्तों के तहत पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी, लेकिन एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया के बीच का अंतर एक विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा वर्तमान स्पष्टीकरण दोनों अवधारणाओं की स्पष्ट समझ प्रदान करने के लिए है।*

मुख्य बिंदु

- **सुप्रीम कोर्ट — यूथेनेशिया:** एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया के बीच अंतर स्पष्ट किया।
- **सुप्रीम कोर्ट — एक्टिव यूथेनेशिया:** एक नई, बाहरी एजेंसी के नुकसान के माध्यम से मृत्यु का कारण बताया।
- **सुप्रीम कोर्ट — पैसिव यूथेनेशिया:** मृत्यु को होने देने के रूप में समझाया।
- **सुप्रीम कोर्ट — यूथेनेशिया बहस:** व्यक्तिगत अधिकारों और चिकित्सा नैतिकता पर इसके प्रभाव की जांच।
- **सुप्रीम कोर्ट — गरिमा के साथ मरने का अधिकार:** 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले में मान्यता प्राप्त।

नीतिगत निहितार्थ

> *सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया पर स्पष्टीकरण के व्यक्तिगत अधिकारों और चिकित्सा नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। दोनों अवधारणाओं के बीच का अंतर भविष्य के चर्चाओं और यूथेनेशिया पर निर्णयों को सूचित करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार संरक्षित है और साथ ही ऐसे निर्णय के नैतिक और नैतिक प्रभावों पर विचार किया जाता है।*

The Hindu

राजनीति एवं शासन

#02

गेनबिटकॉइन घोटाला मामले में सीबीआई ने डार्विन लैब्स के सह-संस्थापक आयुष वर्ष्णेय को गिरफ्तार किया

गेनबिटकॉइन घोटाला मामले में सीबीआई ने डार्विन लैब्स के सह-संस्थापक आयुष वर्ष्णेय को गिरफ्तार किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 13 दिसंबर, 2023 के आदेश के अनुसार है। यह घोटाला कई हजार करोड़ रुपये का है। सीबीआई विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों,包括 डार्विन लैब्स, की भूमिका की जांच कर रही है। जांच जारी है, सीबीआई घोटाले में शामिल जटिल लेन-देन और संस्थाओं को उजागर करने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सीबीआई को मामले की जांच करने और दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए अधिकार दिया है।

पृष्ठभूमि

> *गेनबिटकॉइन घोटाला मामला कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 दिसंबर, 2023 के आदेश ने सीबीआई को मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। यह मामला भारत में क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन के नियमन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।*

मुख्य बिंदु

- **सीबीआई — जांच:** गेनबिटकॉइन घोटाला मामले में डार्विन लैब्स के सह-संस्थापक आयुष वर्ष्णेय को गिरफ्तार किया।
- **सुप्रीम कोर्ट — आदेश:** 13 दिसंबर, 2023 को सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
- **सीबीआई — जांच:** विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों, जिनमें डार्विन लैब्स भी शामिल है, की भूमिका की जांच कर रही है।
- **सीबीआई — कार्रवाई:** घोटाले में शामिल जटिल लेन-देन और संस्थाओं को उजागर करने का काम कर रही है।
- **सुप्रीम कोर्ट — आदेश:** सीबीआई को मामले की जांच करने और दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए अधिकार दिया है।

नीतिगत निहितार्थ

> *गेनबिटकॉइन घोटाला मामले की जांच भारत में क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन के नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। यह मामला इस प्रकार के लेन-देन के नियमन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सीबीआई की जांच और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भारत में क्रिप्टोकरेंसी उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।*

The Hindu

राजनीति एवं शासन · अर्थव्यवस्था · SCHEMES & INITIATIVES

#03

कैबिनेट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता और कंपनी अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दी

कैबिनेट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है। संशोधनों का उद्देश्य दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में सुधार करना और लेनदारों के अधिकारों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करना है। दिवाला और दिवालियापन संहिता, जो 2016 में पेश की गई थी, को उसके प्रारंभ से कई बार संशोधित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013, एक व्यापक कानून है जो कंपनियों के निगमन, प्रबंधन और समापन को नियंत्रित करता है। संशोधनों के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि

> *दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 में दिवालियापन और दिवालियापन के मामलों के समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए पेश की गई थी। कोड को उसके प्रारंभ से कई बार संशोधित किया गया है, जिसमें सबसे हालिया संशोधन 2020 में किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 को भी कई बार संशोधित किया गया है, जिसमें सबसे हालिया संशोधन 2020 में किया गया था।*

मुख्य बिंदु

- **कैबिनेट — दिवाला और दिवालियापन संहिता:** दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में सुधार के लिए संशोधनों को मंजूरी दी।
- **कैबिनेट — कंपनी अधिनियम, 2013:** लेनदारों के अधिकारों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए संशोधनों को मंजूरी दी।
- **कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय — दिवाला और दिवालियापन संहिता:** कॉर्पोरेट क्षेत्र में सुधार के लिए संशोधनों को लागू करेगा।
- **कैबिनेट — दिवाला और दिवालियापन संहिता:** दिवालियापन और दिवालियापन के मामलों के समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान करने का उद्देश्य है।
- **कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय — कंपनी अधिनियम, 2013:** सुनिश्चित करेगा कि संशोधनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

नीतिगत निहितार्थ

> *दिवाला और दिवालियापन संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधनों के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। संशोधनों से लेनदारों के अधिकारों पर अधिक स्पष्टता प्रदान की जाएगी और दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में सुधार होगा, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।*

The Hindu

राजनीति एवं शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · रक्षा एवं सुरक्षा

#04

एसआरएमआईएसटी ने नौसेना अकादमी के साथ तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसआरएमआईएसटी) ने नौसेना अकादमी के साथ तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थान अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों में सहयोग करेंगे, जिसमें संकाय, छात्रों और विद्वान संसाधनों का आदान-प्रदान शामिल है। वे संयुक्त सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन और विशेषज्ञ व्याख्यान भी आयोजित करेंगे। इस सहयोग का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह साझेदारी छात्रों और संकाय के लिए संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान करेगी।

पृष्ठभूमि

> *एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसआरएमआईएसटी) विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोगी अनुसंधान और शिक्षा पहल में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। नौसेना अकादमी ने भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसी तरह के सहयोग में भाग लिया है। यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।*

मुख्य बिंदु

- **एसआरएमआईएसटी — नौसेना अकादमी समझौता ज्ञापन:** तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग।
- **एसआरएमआईएसटी — नौसेना अकादमी समझौता ज्ञापन:** संकाय, छात्रों और विद्वान संसाधनों का आदान-प्रदान।
- **एसआरएमआईएसटी — नौसेना अकादमी समझौता ज्ञापन:** संयुक्त सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन और विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन।
- **एसआरएमआईएसटी — नौसेना अकादमी समझौता ज्ञापन:** प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार।
- **एसआरएमआईएसटी — नौसेना अकादमी समझौता ज्ञापन:** संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अवसर।

नीतिगत निहितार्थ

> *एसआरएमआईएसटी और नौसेना अकादमी के बीच यह सहयोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह साझेदारी छात्रों और संकाय के लिए संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान करेगी, जिससे नवाचारी समाधानों और प्रौद्योगिकियों का विकास होगा।*

The Hindu

अर्थव्यवस्था · कृषि एवं ग्रामीण विकास

#05

आरबीआई ने ₹50,000 करोड़ की जी-सेक्स खरीद की

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बाजार में तरलता को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक्स) की खरीद की है। यह कदम तब उठाया गया है जब रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं। आरबीआई की इस कार्रवाई का उद्देश्य मुद्रा को स्थिर करना और वित्तीय प्रणाली में तरलता बनाए रखना है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक और जी-सेक्स खरीद की घोषणा की है। इन खरीदों के माध्यम से तरलता की कुल राशि के अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि

> *आरबीआई वित्तीय प्रणाली में तरलता को प्रबंधित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है ताकि बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के प्रभावों को कम किया जा सके। केंद्रीय बैंक के पिछले उपायों, जिनमें मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ) की शुरुआत शामिल है, ने धन बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद की है।*

मुख्य बिंदु

- **आरबीआई — जी-सेक्स खरीद:** ₹50,000 करोड़ बाजार में तरलता को बढ़ावा देने के लिए।
- **आरबीआई — जी-सेक्स खरीद:** शुक्रवार को एक और त्रांच की घोषणा की गई है।
- **आरबीआई — मौद्रिक नीति:** मुद्रा को स्थिर करने और तरलता बनाए रखने के लिए।
- **आरबीआई — तरलता प्रबंधन:** तरलता की कुल राशि के अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- **आरबीआई — मुद्रा प्रबंधन:** बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के प्रभावों को कम करने के प्रयास।

नीतिगत निहितार्थ

> *आरबीआई के जी-सेक्स खरीद के निर्णय के अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि यह मुद्रा को स्थिर करने और वित्तीय प्रणाली में तरलता बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि, केंद्रीय बैंक को स्थिति पर निगरानी रखनी होगी और अपनी मौद्रिक नीति को आवश्यकतानुसार समायोजित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है।*

The Hindu

स्वास्थ्य एवं सामाजिक मुद्दे · कृषि एवं ग्रामीण विकास

#06

किसान निधि की अगली किश्त 13 मार्च को किसानों के खाते में आएगी

किसान निधि योजना की 22वीं किश्त 13 मार्च को जारी की जाएगी, जिसमें 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी। कृषि मंत्री ने यह घोषणा की, जिसमें योजना के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया। किसान निधि योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस किश्त के साथ, योजना पूरे देश में महिला किसानों को सशक्त बनाना जारी रखती है। यह किश्त किसानों के खाते में आने से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि

> *किसान निधि योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना कई वर्षों से संचालित है, जिसमें नियमित किश्तें पात्र किसानों को दी जाती हैं, जिनमें महिला किसान भी शामिल हैं जो कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।*

मुख्य बिंदु

- **कृषि मंत्रालय — किसान निधि:** 22वीं किश्त 13 मार्च को जारी की जाएगी।
- **कृषि मंत्रालय — किसान निधि:** 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
- **कृषि मंत्रालय — किसान निधि:** योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **कृषि मंत्रालय — किसान निधि:** किश्त के वितरण से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- **कृषि मंत्रालय — किसान निधि:** यह योजना पूरे देश में महिला किसानों को सशक्त बनाने का काम करती है।

नीतिगत निहितार्थ

> *किसान निधि योजना की अगली किश्त के वितरण से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासकर महिला किसानों के लिए। सरकार का इस योजना के माध्यम से किसानों को निरंतर समर्थन करना कृषि उद्योग के विकास में योगदान देने की संभावना है।*

The Hindu

करेंट अफेयर्स

#07

भारतीय घरों में इंडक्शन स्टोव की धीमी गति

भारतीय घरों में इंडक्शन कुकटॉप्स का उपयोग धीमी गति से हो रहा है, विशेष रूप से निम्न-आय वाले घरों में। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल 5% भारतीय घरों में उनके रसोई में बिजली की प्रवेश है, जो इलेक्ट्रिक खाना पकाने के तरीकों को अपनाने की कमी को दर्शाता है। यह इंडक्शन कुकिंग के संभावित लाभों के बावजूद है, जिसमें ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा शामिल है। इंडक्शन स्टोव की धीमी गति नीति निर्माताओं के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह स्वच्छ और अधिक कुशल खाना पकाने के तरीकों में संक्रमण को बाधित करता है। भारत सरकार इलेक्ट्रिक खाना पकाने के तरीकों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन निम्न-आय वाले घरों में अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक कुछ करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

> *भारत सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों के तहत इलेक्ट्रिक खाना पकाने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑन एन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी शुरू किया है, जो 2008 में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय घरों में ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना है, जिसमें इंडक्शन कुकटॉप्स भी शामिल हैं।*

मुख्य बिंदु

- **विशेषज्ञ — इंडक्शन कुकटॉप्स:** केवल 5% भारतीय घरों में उनके रसोई में बिजली की प्रवेश है।
- **भारत सरकार — राष्ट्रीय मिशन ऑन एन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी:** ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना, जिसमें इंडक्शन कुकटॉप्स भी शामिल हैं।
- **नीति निर्माता — इलेक्ट्रिक खाना पकाने के तरीके:** निम्न-आय वाले घरों में इंडक्शन स्टोव की धीमी गति के बारे में चिंतित हैं।
- **इंडक्शन कुकिंग — ऊर्जा दक्षता:** ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा जैसे संभावित लाभ प्रदान करता है।
- **निम्न-आय वाले घर — इंडक्शन स्टोव:** उच्च अग्रिम लागत और जागरूकता की कमी जैसी बाधाओं का सामना करते हैं।

नीतिगत निहितार्थ

> *निम्न-आय वाले भारतीय घरों में इंडक्शन स्टोव की धीमी गति के महत्वपूर्ण नीतिगत परिणाम हैं, क्योंकि यह स्वच्छ और अधिक कुशल खाना पकाने के तरीकों में संक्रमण को बाधित करता है। इसके लिए नीति निर्माताओं को सब्सिडी या वित्तीय विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि इंडक्शन कुकटॉप्स निम्न-आय वाले घरों के लिए अधिक सुलभ हो सकें। इसके अलावा, नीति निर्माताओं को जागरूकता अभियान शुरू करने और निम्न-आय वाले घरों में इंडक्शन स्टोव के लाभों को बढ़ावा देने की आवश्यकता हो सकती है।*

The Hindu

अंतर्राष्ट्रीय संबंध · अर्थव्यवस्था

#08

इरान ने क्षेत्र में अमेरिकी-इज़राइली आर्थिक, बैंकिंग हितों पर निशाना साधने की घोषणा की

इरान ने घोषणा की है कि वह क्षेत्र में अमेरिकी-इज़राइली आर्थिक और बैंकिंग हितों पर निशाना साधेगा, जो तेहरान में ईरानी बैंक सेपाह पर हुए हमले के बाद हुआ है। यह बैंक ईरान में सबसे बड़े बैंकों में से एक है, जिसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय हित हैं। इस हमले ने ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ते तनावों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जो इसके बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

> *ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच तनाव पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहे हैं, जब अमेरिका ने 2018 में ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों का ईरान की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिससे देश की जीडीपी 2020 में 4.8% घट गई। ईरानी सरकार इन प्रतिबंधों को चकमा देने और अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के तरीके खोज रही है।*

मुख्य बिंदु

- **ईरानी सरकार — आर्थिक प्रतिबंध:** अमेरिकी-इज़राइली आर्थिक हितों के खिलाफ प्रतिशोधी उपायों की घोषणा की।
- **अमेरिकी सरकार — आर्थिक प्रतिबंध:** 2018 में ईरान पर प्रतिबंध लगाए, जो इसके बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं।
- **ईरानी बैंक सेपाह — हमला:** तेहरान में रात्रि में हुआ, जिससे तनाव बढ़ने की चिंताएं बढ़ गईं।
- **ईरानी सरकार — प्रतिशोध:** अमेरिकी-इज़राइली आर्थिक और बैंकिंग हितों पर निशाना साधने का संकल्प लिया।
- **अमेरिका और इज़राइल — आर्थिक हित:** क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक और बैंकिंग हित हैं, जिन पर ईरान ने निशाना साधने की धमकी दी है।

नीतिगत निहितार्थ

> *ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच तनावों के बढ़ने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी-इज़राइली आर्थिक और बैंकिंग हितों पर निशाना साधने से तनाव और बढ़ सकता है, जो क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।*

The Hindu

PRELIMS SPECIAL

#09

जॉन डीरे ने 130 एचपी ट्रैक्टर ₹65 लाख में लॉन्च किया

जॉन डीरे ने 130 एचपी का एक नया ट्रैक्टर लॉन्च किया है। यह ट्रैक्टर कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस, 100% रेडियल टायर, स्ट्रेट-रो व्हीकल गाइडेंस सिस्टम और फ्रंट हिच और फ्रंट पीटीओ एप्लिकेशन जैसी उन्नत विशेषताओं के साथ आता है। इस ट्रैक्टर की कीमत ₹65 लाख है। इस ट्रैक्टर के लॉन्च से कृषि क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ट्रैक्टर की उन्नत विशेषताएं किसानों के लिए दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करेंगी। जॉन डीरे के इस नए ट्रैक्टर में 130 एचपी की शक्ति है।

पृष्ठभूमि

> *भारत में कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक वाले ट्रैक्टरों की मांग में वृद्धि हुई है। सरकार भी कृषि में उन्नत तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। हाल के वर्षों में, भारत में उच्च शक्ति वाले ट्रैक्टरों की बिक्री में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।*

मुख्य बिंदु

- **जॉन डीरे — नया ट्रैक्टर:** 130 एचपी का ट्रैक्टर उन्नत विशेषताओं के साथ लॉन्च किया।
- **जॉन डीरे — नया ट्रैक्टर:** ₹65 लाख में प्राइस्ड।
- **जॉन डीरे — नया ट्रैक्टर:** कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस और 100% रेडियल टायर के साथ आता है।
- **जॉन डीरे — नया ट्रैक्टर:** स्ट्रेट-रो व्हीकल गाइडेंस सिस्टम की विशेषता है।
- **जॉन डीरे — नया ट्रैक्टर:** फ्रंट हिच और फ्रंट पीटीओ एप्लिकेशन शामिल है।

नीतिगत निहितार्थ

> *इस नए ट्रैक्टर के लॉन्च से कृषि क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ट्रैक्टर की उन्नत विशेषताएं किसानों के लिए दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करेंगी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।*

The Hindu

करेंट अफेयर्स

#10

मुख्यमंत्री कोच्चि में ₹3,509 करोड़ के मैरीन ईको सिटी परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे

कोच्चि में मैरीन ईको सिटी परियोजना एक महत्वपूर्ण विकास पहल है, जिसकी कुल लागत ₹3,509 करोड़ है। यह परियोजना शहर के परिदृश्य को बदलने और निवासियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। परियोजना के पहले चरण से क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की उम्मीद है। केरल सरकार कोच्चि को व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए काम कर रही है, और मैरीन ईको सिटी परियोजना इस प्रयास का एक हिस्सा है, जिसमें स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पृष्ठभूमि

> *मैरीन ईको सिटी परियोजना की अवधारणा पहली बार 2019 में प्रस्तावित की गई थी, जिसका उद्देश्य एक भविष्यवाणी शहर बनाना था जो केरल की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करता है। इस परियोजना को हरित प्रौद्योगिकियों को शामिल करने और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह निवेशकों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है।*

मुख्य बिंदु

- **केरल सरकार — मैरीन ईको सिटी परियोजना:** ₹3,509 करोड़ की लागत से पहले चरण का शिलान्यास कर रही है।
- **केरल सरकार — मैरीन ईको सिटी परियोजना:** कोच्चि के परिदृश्य को बदलने और निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए।
- **केरल सरकार — मैरीन ईको सिटी परियोजना:** स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- **केरल सरकार — मैरीन ईको सिटी परियोजना:** क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की उम्मीद है।
- **केरल सरकार — मैरीन ईको सिटी परियोजना:** कोच्चि को व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बनाने के प्रयास का हिस्सा है।

नीतिगत निहितार्थ

> *मैरीन ईको सिटी परियोजना के पूरा होने से कोच्चि की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। परियोजना के स्थिरता और हरित प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने से निवेश आकर्षित होने और नए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है, जो शहर के विकास और विकास में योगदान करेगा।*

The Hindu

त्वरित प्रश्नोत्तर

1. युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए एपीएसएसडीसी और ओएमसीएपी ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

   उत्तर: **अपोलो मेडस्किल्स**

2. कर्नाटक में 'अवैध' डिजिटल विज्ञापन होर्डिंग्स को नियमित करने की योजना के खिलाफ याचिका पर किस न्यायालय ने नोटिस जारी किया है?

   उत्तर: **कर्नाटक उच्च न्यायालय**

3. संसद में प्रस्तावित विधेयक किस संबंध में है?

   उत्तर: **सीएपीएफ में आईपीएस प्रतिनिधि का संवर्धन**

4. कौन सा नियामक निकाय कीवी जनरल इंश्योरेंस और एलियांज जियो रीइंश्योरेंस को मंजूरी दे दी है?

   उत्तर: **इरडा**

5. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से किस राज्य के लोक निर्माण मंत्री को बाहर रखा गया था?

   उत्तर: **केरल**